

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 01 फरवरी 2026, समय 1810 (05 मिनट))

- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। - वित्त मंत्री ने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला बजट बताया।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की।
- बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी।
- बड़े उद्योगों और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए पांच टाऊनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा - केंद्रीय बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करेगा।
- उद्योग एवं वाणिज्य से जुड़े लोगों ने बजट की सराहना की और इसे दूरदर्शी सोच वाला बजट बताया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया। लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, बजट से प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला बजट बताया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रस्ताव किए गए, जिनमें खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने दस हजार करोड़ रुपये के लघु और मध्यम उद्यम - एस एम ई विकास कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा- एस एम ई ऋण लेने वालों के लिए अव-संरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अगले पांच वर्ष के लिए बायो-फार्मा शक्ति के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और वर्तमान सात संस्थानों को उन्नत करने की घोषणा भी की। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी किया। बजट में अगले पांच वर्षों में कंटेनर विनिर्माण योजना

के लिए दस हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव है। बजट में दिए गए अन्य प्रस्तावों की बात करें तो खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण के लिए तीन समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा 12 लाख बीस हजार करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई। अगले पांच वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है, संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी।

केंद्र सरकार विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उच्च-स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्योग स्थाई समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार अखिल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रोत्साहन देगी। मुंबई में 15 हजार माध्यमिक स्कूलों और पांच सौ कॉलेजों में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, और कॉमिक्स का कंटेंट तैयार करने वाली ए.वी.सी.जी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा- बड़े उद्योगों और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए पांच टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। देश के प्रमुख विरासत स्थलों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री ने भारत को मेडिकल टूरिज्म के प्रमुख क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पांच स्थानों को विकसित करेगी। अधिक पेशेवर चिकित्साकर्मी तैयार करने के लिए तीन अन्य अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार, रांची और तेजपुर में निमहंस-2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा आपातकालीन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार, खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अगले एक दशक में खेल जगत का विकास होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट आज की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलेगा और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। एक वीडियो संदेश में, श्री मोदी ने कहा कि यह एक अनोखा बजट है, जो राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने पर केंद्रित है

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश करता है।

उन्होंने कहा कि बजट उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास सुनिश्चित करता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उंची उड़ान भरने का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की परिकल्पना को साकार की एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि बजट रफ्तार, क्षमता और सब का साथ सबका विकास पर केंद्रित है।

हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि केंद्रीय बजट दूरदृष्टि, संतुलन और समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्य सलाहकार विष्णु गोयल ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए यह एक दूरदर्शी सोच वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि बजट में पहली बार कृषि क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के प्रयोग का प्रस्ताव भी सराहनीय है।

आई.एम.एस.एम.ई ऑफ़ इंडिया के फरीदाबाद के अध्यक्ष राजीव चावला ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत की प्रगति की यात्रा और तेज होगी।

कुरुक्षेत्र में लोगों ने बजट में आयुर्वेदिक क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं मेडिकल क्षेत्र के प्रस्तावों और कैंसर जैसे रोगों की दवाएं सस्ती किए जाने को लेकर खुश नजर आए। पंचकूला की एक ग्रहणी चारु मेहता ने महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने के प्रस्ताव की सराहना की।

भिवानी निवासियों ने इसे सभी वर्गों के लिए बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने चिकित्सा व रेलवे के क्षेत्र में देश की उन्नति के लिए बजट में किए गए प्रावधान को सराहा है। बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए भिवानी निवासी रमेश बंसल व सचिन सिंगला ने बताया कि बजट में किसान, महिला, व्यापारी सभी के लिए प्रावधान किया गया है। बजट में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बरकरार रखा गया है।
